

मद्रास में विधि मंत्रालय का शाखा सचिवालय

28. श्री बड़े :

श्री हुकूम चन्ध कछवाय :

क्या विधि मंत्री 24 अगस्त, 1965 के अनारंकित प्रश्न संख्या 509 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में विधि मंत्रालय का शाखा सचिवालय स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

विधि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री जे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) का एक शाखा सचिवालय मद्रास में स्थापित करने की प्रस्तावना इस समय स्थगित कर दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाली घाट पर पुल

29. श्री हुकूम चन्ध कछवाय :

श्री बड़े :

क्या परिवहन, उद्भयन, नौबहन तथा पर्वटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिवपुर (मध्य प्रदेश) और सवाई माधोपुर (राजस्थान) के बीच पाली घाट पर चम्बल नदी पर पुल का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है; और

(ख) उक्त पुल के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उद्भयन, नौबहन तथा पर्वटन मंत्री (श्री लंजीव देवू) : (क) और(ख)। चूंकि सवाई माधोपुर शिवपुर सड़क पर चंबल

नदी के ऊपर पालीघाट पर का प्रस्तावित पुल राज्य सड़क पर पड़ता है अतः वह राज्य परियोजना है। इसलिये इसके निर्माण की जिम्मेदारी मुख्यतः संबद्ध राज्य सरकारों की है। परन्तु अन्तर्राज्यिक संचार सुविधाओं को बढ़ावा देने की दृष्टि से जून, 1964 में अन्तर्राज्यिक पुलों के, जिनमें राजस्थान—मध्य प्रदेश सीमान्त क्षेत्र में पालीघाट पर चंबल नदी का प्रस्तावित पुल भी शामिल है, सर्वेक्षण, जलीय भ्रंशकों को हकट्टा करने, स्थान निश्चित करने जैसे प्रारम्भिक कामों के लिए तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में केन्द्रीय सहायता देने की व्यवस्था करने का तय किया गया था। इन पुलों के वास्तविक निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करने के प्रश्न पर चौथी पंचवर्षीय आयोजना में विचार किया जाना था। तदनुसार पालीघाट पर चंबल नदी के प्रस्तावित पुल और राजस्थान के दो अन्य पुलों के सर्वेक्षण के लिए नवम्बर, 1965 में कुल 1,216,00 रु० का अनुमान मंजूर किया गया था। इन प्रारम्भिक जांचों के पूरा होने के बाद इस पुल तथा ऐसे ही अन्य पुलों के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करने के प्रश्न पर चौथी पंचवर्षीय आयोजना में ऐसी परियोजनाओं के लिए धन की उपलब्ध अनुसार विचार किया जायेगा।

कोयले का मूल्य

30. श्री बड़े : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री 7 दिसम्बर, 1965 के तारकित प्रश्न संख्या 684 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी स्टोर द्वारा कोयला खानों से किस दर पर कोयला खरीदा गया था और जनता को किस दर पर बेचा गया था; और